

2



प्रभारी मंत्री
लखन पटेल ने
की शस्त्र पूजा

3



प्रवीण कवकड़
की पुस्तक का
विमोचन

5



भारत के
अनमोल रतन :
रतन टाटा

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 15 अंक : 23

प्रति सोमवार, 14 अक्टूबर 2024

मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

पक्के आवास, किसानों को बोनस और महिलाओं को सौगात, देने के लिए प्रतिबद्ध हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

भूपेश सरकार के जख्मों से जनता को मिल रही राहत

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार को लगभग आठ माह हो गये हैं। इन आठ माह में प्रदेश की सरकार ने जनकल्याण के कई कार्य किये हैं या प्रारंभ कर दिये हैं। सभी जनकल्याणकारी योजनाओं पर एक साथ

काम कर रही है। स्कूल, स्वास्थ्य, नक्सलवाद, सड़क, बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों युद्ध स्तर पर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनकल्याण के कार्यों में पूरी तरह संलग्न होकर सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। यही कारण है कि राज्य में हर तरफ अब हरियाली और चहलू और विकास की नई तस्वीर दिखाई दे रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी और केन्द्र सरकार को आभार प्रकट किया है। सीएम ने बताया कि छत्तीसगढ़ को भारत सरकार ने 08 लाख 46 हजार 931 प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति दी है। उन्होंने इसे प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। इससे



छत्तीसगढ़वासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए और कष्टने होंगे प्रयास

लाखों गरीब परिवारों को अपने सिर पर छत का सपना साकार करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के 18 लाख से अधिक गरीब परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गए थे क्योंकि तत्कालीन सरकार ने इस योजना के लिए आवश्यक राज्यांश 40 प्रतिशत जमा नहीं किया था। इस वजह से इन गरीब परिवारों का हक छीना गया था। निश्चित ही पिछली भूपेश सरकार के द्वारा दिये गये जख्मों से जनता को राहत मिल रही है। आमजन ने बदलाव कर प्रदेश को एक नई दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन साय सरकार प्रदेशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है। भूपेश शासन में प्रदेश को जो पीछे पहुंच चुका है उसे आगे लाने में बहुत कुछ करना होगा। हम मानते हैं कि सरकार जिस तेजी के साथ कामों को आगे बढ़ा रही है, निश्चित ही यह एक सही दिशा है। इस दिशा में सरकार को उन पहलुओं को भी ध्यान में रखना होगा जो पिछले कई वर्षों से अनछुए रहे हैं। रोजगार, कौशल विकास, नक्सलवाद, नारी शक्ति, किसान कल्याण, आदिवासी उत्थान जैसे अनेक मामले हैं जिन पर सरकार को युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। (शेष पेज 7 पर)

जनजातीय वनवासियों के हितों के संरक्षण के लिए साय सरकार के प्रयास वनस्पति और जीवों के पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने के लिए ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की पहल

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा राज्य में जनजातीय वनवासियों के हितों के संरक्षण के लिए और पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए लगातार महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वनमंत्री केदार करयप ने जनजातीय समुदायों के युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता को बखूबी समझा है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में इन समुदायों को सशक्त बनाने एवं छत्तीसगढ़ राज्य की समृद्ध प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की गई है।

ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम

छत्तीसगढ़ वन विभाग ने हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक अनूठा कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है।

(शेष पेज 7 पर)

क्या मंदसौर, नीमच, रतलाम में बेरोकटोक ड्रग मूवमेंट पर सरकार का है संरक्षण ?

मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के संरक्षण में चल रहे एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का हुआ पर्दाफाश!

-विजया पाठक

आज मध्यप्रदेश भारत में ड्रग्स मैनु फैक्ट्रिंग के मामले में कोलंबिया को टक्कर दे रहा है। नीमच, रतलाम, मंदसौर में अवैध नेचुरल ड्रग्स जैसे कोकीन, हीरोइन इत्यादि की अवैध फैक्ट्रियां सरकार में बैठे मंत्रियों के संरक्षण में चल ही रहा था पर भोपाल स्थित एक फैक्ट्री से सिंथेटिक ड्रग्स का रैकेट का खुलासा होने के बाद

मध्यप्रदेश का नाम इस गंदे कारोबार से भी जुड़ गया है। इस सिंथेटिक ड्रग्स माफिया का मास्टरमाइंड मंदसौर का रहने वाला हरीश आंजना है। मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का खास व्यक्ति के हरीश आंजना की डेरों तस्वीरें कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक की हैं। हरीश द्वारा उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों

आखिर कौन है मध्यप्रदेश का पाबलो एस्कोबार?



में डेरों पैसे खर्च किए गए एवं सूत्रों द्वारा इनके बेटे हर्ष के काफी करीबी हरीश आंजना बताए गए हैं। जगदीश देवड़ा के पुत्र हर्ष के विवाह के सारे कार्यक्रमों में हरीश मौजूद था, इन सबसे स्पष्ट होता है कि हरीश आंजना के मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा एवं उनके परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। अब सवाल यह है कि किसकी शह पर ड्रग माफिया हरीश आंजना को बेरोकटोक मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर और भोपाल में तस्करी करता था।

(शेष पेज 6 पर)

क्या उज्जैन से मिल रहा है बड़े ड्रग माफियाओं को संरक्षण ?

लाल आतंक का साथ छोड़ने वाले आत्म समर्पित नक्सलियों का घर बसाएगी छत्तीसगढ़ सरकार, स्वरोजगार के लिए मिलेगा लोन

-संवाददाता

जगत प्रवाह, रायपुर।

आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास की नीति राज्योत्सव के अवसर पर लांच होगी। इसके प्रमुख प्रविधानों के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार मुख्याधारा से जुड़ने वालों का घर बसाएगी। उन्हें उनकी जरूरत की सभी चीजें दी जाएंगी। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और उनके स्वजन विकास के लिए सरकार अलग से बजट भी निर्धारित करेगी।



पुनर्वास की नीति के ज्यादातर प्रविधान असम से लिए गए हैं। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री विजय शर्मा ने असम का दौरा करके यहां अध्ययन किया है और वहां की नीति का 80 प्रतिशत हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जा सकता है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए हमारी सरकार उनके

आवास की व्यवस्था करेगी। सरकार की सभी योजनाओं के लाभ तो मिलेगा ही साथ ही उनके लिए विशेष नीति हम जल्द ही लांच कर लेंगे।

पुनर्वास नीति इसलिए जरूरी

रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार जिस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में खासकर असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागलैंड

और त्रिपुरा में आतंकवादियों के आत्मसमर्पण व पुनर्वास की नीति के बाद यहां आतंकवाद में नियंत्रण पाया गया है, उसी फार्मूले से छत्तीसगढ़ में भी नक्सलियों का अंत किया जा सकता है। इसके लिए पुनर्वास नीति बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे गुमराह युवक जो कि हार्डकोर नक्सलियों के दुष्क्रम में फंस गए हैं। उन्हें मुख्याधारा में लाने के बाद वह दोबारा नक्सलियों के चंगुल में न फंसे इसे रोकने की चुनौती होगी।

पिछले नौ महीनों में लगातार कार्रवाई

नक्सलियों के खिलाफ साय सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ में 194 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा गया है। 801 नक्सली गिरफ्तार और 742 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।



दिवाली से पहले छत्तीसगढ़ के इन कर्मचारियों को बड़ी सौगात, जारी हुआ समयमान वेतनमान का आदेश

-संवाददाता

जगत प्रवाह, रायपुर।

प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 421 अभियंताओं को उनके दीर्घकालीन सेवा योगदान का सम्मान करते हुए समयमान वेतन का लाभ प्रदान करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के अंतर्गत 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले 32 अभियंता, 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले 388 अभियंता, और 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले 01 अभियंता शामिल हैं। इन अभियंताओं

में उप अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि यह प्रकरण पिछले 4-5 वर्षों से लंबित था और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देशों के परिणामस्वरूप अब जाकर इन अभियंताओं को समयमान वेतन का लाभ मिल रहा है। उपमुख्यमंत्री शर्मा के निर्देशानुसार अभियंताओं को समयमान वेतन का लाभ दिया है, जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं और प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।



प्रभारी मंत्री लखन पटेल ने की शस्त्रों की पूजा

-कैलाशचंद्र जैन

जगत प्रवाह, बिड़िया प्रदेश के

पशुपालन एवं डेयरी स्वतंत्र राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री लखन पटेल ने विदिशा पुलिस लाइन में दशहरा पर्व पर आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम में शामिल होकर विधिविधान से पूजन-अर्चना की है। इस अवसर पर कुरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे, शमशाबाद विधायक सूर्य प्रकाश मोणा, कलेक्टर रौशन कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के अलावा अन्य जन्मप्रतिनिधि गण, अपर कलेक्टर अनिल कुमार डामोर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चैबे समेत विभिन्न विभागों के

अधिकारी- कर्मचारीगण, मीडिया कर्मी मौजूद रहे। पुलिस लाइन में आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम में पुलिस द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के शस्त्रों को रखा गया था। जिसमें विशेष तौर पर पहली बार साइबर अपराधों के नियंत्रण व धरपकड़ में उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स विंग को भी रखा गया था। प्रभारी मंत्री श्री पटेल, विधायक इय, कलेक्टर व एसपी सहित अन्य के द्वारा हवन में शामिल होकर आहुतियां दी हैं। इसके पश्चात बलि के प्रतीक स्वरूप तलवार से रखिया को एक ही वार में काटा। प्रभारी मंत्री पटेल ने पुलिस लाइन में वाहनों

की भी पूजा की तथा महिलाओं को त्वरित मदद के लिए जारी टोल फ्री नम्बरों के साइन तख्ती का विमोचन किया। गौरतलब हो कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किए जा रहे प्रबंधों को रेखांकित किया गया था। शस्त्र पूजन कार्यक्रम में विदिशा नगरपालिका उपाध्यक्ष संजय दिवाकीर्ति, सदीप डोंगर सिंह, राकेश शर्मा कैलाश रघुवंशी, एसडीएम, तहसीलदार, के अलावा पुलिस सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी और मीडिया बंधु मौजूद रहे।

(जगत फीचर्स)

छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय दौरे पर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, IIT और NIT के दीक्षा समारोह में होंगी शामिल

-संवाददाता

जगत प्रवाह, रायपुर।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ में दो दिवसीय दौरे का कार्यक्रम तय हो गया है, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति 25 और 26 अक्टूबर को विभिन्न शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के प्रवास की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को राजभवन में बैठक हुई, जिसमें राज्यपाल रमेश डेका के सचिव यशवंत कुमार ने निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार अधिकारियों को तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति एम्स, एनआईटी रायपुर, आईआईटी भिलाई और पं. दीनदयाल स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान आयुष विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। सचिव यशवंत कुमार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों में

आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही रायपुर और दुर्ग जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, राज्य प्रोटोकाल के अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियां निर्धारित समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में राज्यपाल की संयुक्त सचिव हिना अनिमेष नेताम, रायपुर मेडिकल के डीन डा. विवेक चौधरी आदि अधिकारी मौजूद थे।

राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति दौरे को लेकर चर्चा

मुख्याधिका विष्णुदेव साय ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल रमेश डेका से मुलाकात की और नवरात्रि की शुभकामना दी। बताया जाता है कि राज्यपाल डेका और मुख्यमंत्री साय के बीच राष्ट्रपति मुर्मू के दौरे को लेकर चर्चा हुई।





प्रवीण कक्कड़ की पुस्तक “दंड से न्याय तक” का विमोचन

-संवाददाता

जगत प्रवाह. इंदौर। मध्यप्रदेश की चर्चित शक्तिशाली में से एक प्रवीण कक्कड़ की बहुप्रचारित और बहुप्रतिष्ठित पुस्तक 'दंड से न्याय तक' का विमोचन 6 अक्टूबर को मध्यप्रदेश पुलिस के पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री एसके दास, सीबीआई के स्पेशल प्रोसेक्यूटर श्री मनोज द्विवेदी जी एवं साहित्यकार पंकज सुबौर के हाथों संपन्न हुआ। विमाचन समारोह में पुलिस, पत्रकार, साहित्यकार और इंदौर समेत मध्यप्रदेश के कई गणमान्य नागरिक शामिल हुए। इंदौर की होटल श्रीमाया रेजिडेंसी में संपन्न आयोजन में पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री दास ने कहा कि समाज को यह जानना जरूरी है कि कानून क्या है उनके अधिकार क्या हैं और अपने अधिकारों का उपयोग व कैसे कर सकते हैं। यह पुस्तक बहुत ही सही अवसर पर आई है। आज कानून में परिवर्तन को समझने की पूरे समाज को जरूरत है। अंग्रेजों के जमाने में जैसा आमजन को पुलिस से डर लगता था वह काफी हद तक खत्म हुआ है। पूरी तरह खत्म होने की दिशा में यह पुस्तक सार्थक कड़ी होने का कार्य करेगी।

विशेष अतिथि श्री मनोज द्विवेदी ने कहा कि कानून आमजन को सोशल जस्टिस

दिलाने के लिए है। इसी पहल को लेकर नया कानून आया है। व्यक्ति कानून का जानकार रहेगा तो अपराध कम होंगे। इस विषय पर अब तक कोई पुस्तक नहीं आई है। ऐसे में कानून को समझने के लिए और धाराओं की जानकारी लेने के लिए यह पुस्तक उपयोगी साबित होगी। उन्होंने प्रवीण जी के टाइम मैनेजमेंट की तारीफ करते हुए कहा कि इन्हें हम पुलिस सेवा में भी समय प्रबंधन के लिए जानते थे, मंत्रालय और सचिवालय में भी इसी की चर्चा थी। शिवना प्रकाशन के पंकज सुबौर ने पुस्तक पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पुस्तक सिर्फ पुलिस अधिकारियों के लिए ही नहीं बल्कि हर आमजन के लिए महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक बताती है कि कानून में कौन-कौन सी धाराएं बदल गई हैं। सोशल मीडिया के तूफान के बीच इस पुस्तक का आना एक सार्थक पहल है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रवीण जी को लोग एक पूर्व पुलिस अधिकारी और पूर्व ओएसडी के रूप में तो जानते ही हैं लेकिन एक लेखक के रूप में अब उनकी यह नई पहचान बनेगी। पुस्तक के लेखक श्री प्रवीण कक्कड़ ने पुस्तक को अपनी मां स्वर्गीय विद्यादेवी कक्कड़ को समर्पित करते हुए कहा कि मेरा जीवन पुस्तकालय से शुरू हुआ था कॉलेज में मैं काफी किताबें पढ़ता था। फिर

पुलिस मुख्यालय, सचिवालय और मंत्रालय से होता हुआ फिर पुस्तकालय तक पहुंच गया है। जीवन में काफी उतार चढ़ाव आते हैं लेकिन जब भी आपको आगे बढ़ना हो तो आपको वह सीढ़ी छोड़ना पड़ेगी जिस पर आप मजबूती से खड़े हैं, अपने कंपट जोन से बाहर निकलेंगे, तभी आप ऊपर की ओर बढ़ पाएंगे। उन्होंने पुस्तक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस के नये कानून 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (बीएनएसएफ) और पुराने कानून 'भारतीय दंड संहिता' (आईपीसी) के बीच के बदलाव को मैंने बेहद सरल भाषा में अंकित किया है। यह पुस्तक पुलिस, प्रशासन, कानून के विद्यार्थियों और वकीलों के साथ साथ आम जनता के लिये भी बेहद उपयोगी साबित होने वाली है। इस पुस्तक में पुराने और नए कानून में धाराओं के परिवर्तन, ऑनलाइन शिकायत सहित अन्य महत्वपूर्ण बदलाव की जानकारी है। इसके साथ ही दुनिया की बेस्ट पुलिसिंग सिस्टम और पुलिस सुधार के विभिन्न प्रयासों का भी उल्लेख है। कार्यक्रम में स्वागत भाषण श्रीमती ज्योति जैन ने दिया। उन्होंने शिवना प्रकाशन परिवार की ओर से सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम के सूत्रधार संजय पटेल जी थे।

शौकत महल: इस्लामिक और यूरोपियन शैली का मिश्रित रूप



-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. भोपाल। भोपाल स्थित शौकत महल शहर के बीचोबीच चौक एरिया के प्रवेश द्वार पर स्थित है। यह महल इस्लामिक और यूरोपियन शैली का मिश्रित रूप है। यह महल लोगों की पुरातात्विक जिज्ञासा को जीवंत कर देता है। महल के निकट ही भव्य सदर मंजिल भी बनी हुई है। कहा जाता है कि भोपाल के शासक इस मंजिल का इस्तेमाल पब्लिक हॉल के रूप में करते थे। इस महल का निर्माण सन् 1830 ई. में भोपाल राज्य की प्रथम महिला शासिका नवाब कुदसिया बेगम ने कराया था। यह महल इस्लामिक और यूरोपियन शैली का मिश्रित रूप है। यहाँ परिचामी वास्तु और इस्लामी वास्तु का नायाब संगम है। शौकत महल समन्वयवादी स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस महल का आकल्पन एक फ्रान्सीसी वास्तुविद ने किया था। यह महल लोगों की पुरातात्विक जिज्ञासा को जीवंत कर देता है। इस महल में नवाब जहांगीर मोहम्मद खान और उनकी बेगम नवाब सिकन्दर जहाँ अपने शुरुआती दौर में रहे थे। उनके बाद शासिका बनने के पहले शाहजहाँ बेगम अपने शौहर नवाब उमराव दुल्हा के साथ रहती थीं। शौकत महल के सामने एक विशाल गुलाब उद्यान था।

पुरखों का हिस्सा था शौकत महल- भोपाल के इतिहासकार सैयद अख्तर हुसैन बताते हैं, 'यह महल दो हिस्सों में बंटा था। पुरखों के लिए बना मर्दाना हिस्सा शौकत महल कहलाता था। वहीं, महिलाओं के लिए बने जनाना हिस्से को जिनत महल कहा जाता था। नवाब गौहर महल कुदसिया ने 1819 से 1837 तक भोपाल पर शासन किया था। इसी दौरान उन्होंने यह महल अपनी बेटी सिकंदर बेगम को देने के लिए बनवाया था। सिकंदर बेगम की शादी जहांगीर मोहम्मद खां से हुई थी, जो कुदसिया बेगम के बाद भोपाल के नवाब बने और 1837 से 1844 तक शासन किया।'

70 साल से नहीं खुला एक दरवाजा- अब यह महल प्राइवेट प्रॉपर्टी बन चुका है। इसका एक दरवाजा तो खुला रहता है, लेकिन एक अन्य दरवाजा करीब 70 सालों से बंद है। पिछले 70 साल में यह दरवाजा कभी नहीं खुला। अब इस दरवाजे के सामने अतिक्रमण हो गया है।

महिलाओं के लिए था खुला आंगन- आज जिसे भोपाल में इकबाल मैदान के नाम से जाना जाता है, वह मैदान शौकत महल, मोती महल, गौहर महल का आंगन था और इसका उपयोग नवाब खानदान की महिलाएं सैर के लिए करती थीं। महिलाएं सुह-शाम यहां इकट्ठे होकर बातचीत करती थीं और घूमती थीं। भोपाल का प्रसिद्ध ताजमहल पैलेस बनने के दौरान दूसरी महिला नवाब शाहजहाँ बेगम भी कुछ समय तक इसी महल में रहीं थीं। महल के एक हिस्से में बड़ी दरार आ गई थी, इसलिए नगर निगम ने इसे गिराने का फैसला लिया।

अतिथि शिक्षकों के लंबित वेतन का भुगतान करने की मांग

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। मप्र ऑल इंडिया बेक वर्ड क्लासेस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी एवं मप्र अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी संगठन जिला नरसिंहपुर ने अतिथि शिक्षकों का लंबित मानदेय तत्काल भुगतान की मांग की है। शिक्षा विभाग के आला अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी, सम्पत्त जिले के विकासखंडों के खंड शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य से मांग की अतिथि शिक्षकों की परीक्षा ना लें। सम्पूर्ण नरसिंहपुर जिले के अतिथि शिक्षक नियमित शिक्षकों की तरह सम्पूर्ण लगन से पिछले 16 वर्षों से पढ़ाई करा रहे हैं। जिले के प्राथमरी, माध्यमिक, हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्य कर रहे हैं। पूर्ण निष्ठा लगन के साथ, लेकिन अल्प मानदेय वाले अतिथि शिक्षकों का अगस्त, सितंबर, माह का मानदेय ना मिलने से असंतोष व्याप्त है। (जगत फीचर्स)

12 एकड़ की कृषि मंडी बनी खेल का मैदान

-समीर शास्त्री

जगत प्रवाह. भोपाल। इंदौर-भोपाल मार्ग पर स्थित भैसाखेड़ी कृषि उपज मंडी में साल में सिर्फ एक बार ही खरीदी होती है। जबकि यह मंडी काफी बड़ी है और करीब 12 एकड़ में फैली है। मंडी में साल में केवल गेहूँ की समर्थन मूल्य पर खरीदी होती है बाकी समय यह मंडी वीरान पड़ी रहती है। मंडी में खरीदी न होने के कारण क्षेत्र के किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मजबूरी में किसानों को दूसरी मंडियों में जाकर अपनी उपज को बेचना

पड़ता है। खरीदी न होने के कारण और वीरान पड़े रहने के कारण यहां असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा लगा रहता है। दिन में बच्चों का खेल मैदान बन जाता है। आपको बता दें कि इस मंडी का निर्माण करीब 25 साल पहले हुआ था। हालांकि यह भी बताया जाता है कि मंडी में गोदाम न होने के कारण भी खरीदी नहीं हो रही है। क्योंकि व्यापारियों को अपना अनाज रखने की व्यवस्था नहीं है। 10 साल पहले यहां पर गोदाम बनाने के निर्देश दिये गये थे लेकिन आज तक यहां पर गोदाम नहीं बना है।



सम्पादकीय

सामाजिक आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में क्रान्तिकारी कदम

भारत को पोलियो से मुक्त होने का गौरव हो सकता है, तो देश में एक मजबूत प्रधानमंत्री और सरकार होने पर गौरव के साथ खुशी क्यों नहीं हो सकती है? लेकिन इन दिनों राजनीति के अलावा भी कुछ लोग हैं, जो कमजोर और गठबंधन की सरकार को तमना के साथ वैसी स्थिति के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसका एक कारण लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो क्षेत्रीय दलों का सहयोग लेना पड़ रहा है। सरकार के कुछ निर्णयों को संसद में तत्काल पारित कर लागू करने के बजाय संसदीय समिति आदि से विस्तृत विचार और जखरत होने पर संशोधन के लिए रखा दिया गया। लेकिन इस रूख से प्रधानमंत्री को कमजोर तथा सरकार पांच साल नहीं चल सकने के दावे करके देश विदेश में भ्रम पैदा किया जा रहा है। जबकि अब लोकसभा और राज्य सभा में भी पर्याप्त बहुमत होने से सरकार महत्वपूर्ण विधेयक पारित करवा सकेगी। संविधान में बड़ा संशोधन किए बिना सरकार सामाजिक आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर क्रान्तिकारी बदलाव के फैसले संसद से पारित कर लागू कर सकती है।

प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक की सरकारों के कार्यकाल का गहराई से विश्लेषण किया जाए तो यह साबित हो सकता है कि इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक साहसिक फैसले किए। पहला परमाणु परीक्षण हो या बैंकों और कोल इंडिया का राष्ट्रीयकरण या 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद बांग्लादेश का निर्माण, क्या कमजोर नेतृत्व की सरकार से संभव था। उन निर्णयों को गलत कहने वाले लोग रहे हैं। हां इमरेंसों बहुत बड़ी राजनीतिक गलती थी, लेकिन यह प्रधानमंत्री के कमजोर होने की परिणति थी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी, जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने, तत्काल व्यवस्था विरोधी कानून, संसद और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान का आरक्षण, ब्रिटिश राज के काले कानूनों के बजाय नई न्याय संहिता लागू करने जैसे क्रान्तिकारी बदलाव अपने दृढ़ संकल्प और पर्याप्त बहुमत के बल पर किए। आजादी के बाद कोई प्रधानमंत्री इतने बड़े कदम नहीं उठा सके। इससे पहले 1967 (इंदिरा गांधी), 1977-1979 (मोरारजी देसाई और चरण सिंह), 1989-1991 (वीपी सिंह, चंद्रशेखर), फिर

1999 तक नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच डी देवेगौड़ा इंदुकुमार गुजराल तक की कमजोर सरकारों से कोई बड़े निर्णय नहीं हो सके। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की गठबंधन की सरकारों में खींचातानी, घोटालों की मजबूरियों से न केवल राजनीतिक पतन बल्कि आर्थिक विकास में कठिनाइयां आईं। गठबंधन के कारण वाजपेयी और मनमोहन सिंह को कई क्षेत्रीय नेताओं के दबाव और भ्रष्टाचार को झेलना पड़ा। इसे राजनीतिक चमत्कार ही कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के दस वर्षों के कार्यकाल में किसी एक मंत्री के विरुद्ध घोटाले का कोई प्रामाणिक आरोप सामने नहीं आ सका। राहुल गांधी या अन्य विरोधी नेता सरकार पर अनेक आरोप लगाते रहे, फिर भी जनता ने तीसरी बार मोदी की सरकार बनवा दी। केंद्र से अधिक राज्यों में कमजोर मुख्यमंत्रियों तथा दल बदल की अस्थिर सरकारों से राजनीति से अधिक नुकसान सामाजिक और आर्थिक विकास में हुआ। दिलचस्प बात यह है कि 1956 में केरल से दलबदल की शुरुआत हुई और बहुमत वाली कांग्रेस को धक्का लगा। इसके बाद तो केरल में कम्युनिस्ट पार्टियों, मुस्लिम लीग और स्थानीय पार्टियों के गठबंधन की सरकारों तथा कांग्रेस गठबंधन की दोस्ती दुश्मनी का खेल चलता रहा। वह आज भी जारी है। राज्य और केंद्र में दोनों के चेहरे या मुछोटे अलग-अलग हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता के लिए भ्रम जाल ही कहा जा सकता है। हाल के चुनाव में भी राहुल गांधी के विरुद्ध मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा किया, परिचय बंगाल में भी यही किया। जबकि केंद्र के लिए बने कथित गठबंधन में साथ रणनीति बनाते रहे। दुनिया में ऐसा राजनीतिक मजकूर और धोखा शायद ही देखने को मिले। उनके लिए सत्ता का खेल है, लेकिन इस तरह की स्थितियों से केरल अन्य पड़ोसी दक्षिण के राज्यों से आर्थिक विकास में पिछड़ता गया। साबरता में अग्रणी और योग्य लोगों को बड़ी संख्या में खाड़ी के देशों में नौकरी तथा अन्य काम धंधों के लिए दुनिया भर में जाना पड़ा। यही स्थिति परिचय बंगाल में हुई, जहां कांग्रेस, कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी, वृणमूल कांग्रेस के माया जाल से सत्तार के दशक तक रहे उधोग धंधे भी बर्बाद हुए और टाटा बिड़ला जैसे उद्योगपति तक अपने उद्योग अन्य राज्यों में ले गए।

सियासी गहमागहमी

पटवारी पर जल्द गिर सकती है गाज



मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के अडियल रवैये की शिकायत कांग्रेस आलाकमान तक पहुंच गई है। जाहिर है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में पार्टी सदस्यों की खिन्नता का परिणाम भुगतना पड़ा। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान शीघ्र ही देश के बड़े राज्यों में पार्टी में बड़े पदों पर फेरबदल कर सकती है। चर्चा इस बात की भी है कि पार्टी आलाकमान चाहता है कि प्रदेश का नेतृत्व ऐसे हाथों को मिले जो पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट लेकर चले। ऐसे में पटवारी द्वारा किये गये दुर्व्यवहार की जानकारी पार्टी आलाकमान को मिलने के बाद अंदेशा लगाया जा रहा है कि पटवारी पर जल्द ही गाज गर सकती है।

आखिर शिवराज की प्रदेश की सक्रियता का क्या मतलब



मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की लगातार प्रदेश में सक्रियता को लेकर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। पिछले दिनों शिवराज सीहोर जिले के भेरुंदा में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। ऐसे में चर्चा शुरू हो गई है कि शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के बुदनी सीट से अपने बेटे काटिकिय को टिकट दिलाने के लिये लगातार प्रदेश में सक्रिय बने हुए हैं। हालांकि इस बात की भी चर्चा हो रही है कि शिवराज सिंह चौहान की लगातार प्रदेश में सक्रियता का सीधा प्रभाव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कार्यशैली और उनकी लोकप्रियता पर पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि डॉ. मोहन यादव व भाजपा इस सक्रियता पर क्या कार्यवाही करती है।

हपते का कार्टून

हमें आप पर गर्व है रतन...



ट्वीट-ट्वीट

जम्मू-कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया - प्रदेश में INDIA की जीत सिद्धान्त की जीत है, लोकतांत्रिक स्वामिनाम की जीत है।

हम हरियाणा के अपारवाहित नतीजे का विरलेक्षण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकारियों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे।
-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi



देरा के प्रतिष्ठित उद्योगपति और समाजसेवी पद्म विभूषण श्री रतन टाटा के निधन पर मैं गहरा शोक व्यक्त करता हूँ।



आपनी औद्योगिक दृष्टता से उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया। उनके निधन से देश ने एक प्रतिबद्ध औद्योगिक नेतृत्व खो दिया है।

-कमलनाथ

पेट्टा कार्डेस 38233

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

रतन टाटा को जाता है देश में उद्योग क्रांति लाने का श्रेय

समता पाठक/जगत प्रवाह



दिग्गज उद्योगपति और टाटा संस के चेयरमैन एमेरिटस, रतन टाटा का निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे काफी समय से अवस्थ चल रहे थे। टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने एक बयान में रतन टाटा के निधन की पुष्टि करते हुए उन्हें अपना 'दोस्त, मार्गदर्शक और प्रेरणास्रोत' बताया। रतन टाटा 28 दिसंबर 2012 को टाटा संस के चेयरमैन के रूप में रिटायर हुए थे। टाटा परिवार का देश के विकास में बड़ा योगदान है और रतन टाटा ने भी अपने फैसलों से अपने परिवार की इस महान विरासत को कायम रखा। टाटा परिवार के विभिन्न लोगों ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व से टाटा समूह को इस देश का सबसे प्रमुख और प्रभावशाली व्यापारिक घराना बनाया। साल 1937 में जन्मे रतन टाटा का पालन-पोषण 1948 में उनके माता-पिता के अलग होने के बाद उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। रतन टाटा साल 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बी.आर्क की डिग्री प्राप्त की थी। 1962 के अंत में भारत लौटने से पहले उन्होंने लॉस एंजिल्स में जोन्स और इमन्स के साथ कुछ समय काम किया। 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पद्म विभूषण, प्रदान किया था। वह 28 दिसंबर 2012 को टाटा संस के चेयरमैन के रूप में रिटायर हुए थे।

रतन टाटा की उल्लेखनीय यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने साल 1991 में ऑटोमोबाइल से लेकर स्टील तक के विभिन्न उद्योगों में फैले टाटा समूह की बागडोर संभाली। साल 1996 में उन्होंने टाटा टेली-सर्विसेज की स्थापना की और 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध करवाया, जो कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। टाटा टी द्वारा 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर में ब्रिटिश चाय कंपनी टेटीली का अधिग्रहण किया गया। यह भारतीय कंपनी का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय अधिग्रहण था। टाटा स्टील ने 6.2 बिलियन पाउंड में यूरोपीय की दूसरी सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया। यह भारतीय स्टील उद्योग का अब तक का सबसे बड़ा सौदा था। टाटा मोटर्स ने 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर में प्रतिष्ठित ब्रिटिश कार ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। यह सौदा टाटा मोटर्स के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुआ और कंपनी को वैश्विक ऑटोमोबाइल बाजार में मजबूती दी। रतन टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद, टाटा ग्रुप की कमान एन चंद्रशेखरन के हाथों में है। उन्होंने 2017 में टाटा संस के चेयरमैन का पदभार संभाला था। एन चंद्रशेखरन इससे पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं।



जगत प्रवाह. भोपाल। सस्टेनेबिलिटी यानी प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह उपयोग करना कि वे वापस प्रकृति में लौट सकें। या यूँ समझें वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना और साथ ही यह सुनिश्चित करना कि भविष्य की पीढ़ियाँ भी अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। दुनिया तेजी से बदल रही है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और उपभोक्तावाद की इस दौड़ में मानवता ने कई महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की हैं, लेकिन इन उपलब्धियों की कीमत हमारे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों ने चुकाई है। आज, जब हम अपने आसपास के वातावरण की ओर देखते हैं, तो हमें एक बात स्पष्ट होती है। अगर हमने अभी भी अपनी जीवनशैली और उपभोग के तरीकों में बदलाव नहीं किया, तो हमारा भविष्य अस्थिर होगा। सस्टेनेबल विकास (सतत विकास) का मतलब केवल पर्यावरण की सुरक्षा नहीं है; इसका संबंध एक ऐसे संतुलित विकास से है जो पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के बीच तालमेल बैठाकर सभी की भलाई सुनिश्चित करे। इसके लिए आर्थिक, पर्यावरणीय, और सामाजिक इन तीन क्षेत्रों में नीतियों को एक साथ काम करना होगा। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर जगह देखा जा सकता है। तापमान में वृद्धि, समुद्र के जलस्तर का बढ़ना, और चरम मौसम की घटनाएँ, जैसे बाढ़, सूखा और चक्रवात। इन सबका परिणाम न केवल पर्यावरणीय हानि में होता है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता भी बढ़ती है। कृषि उत्पादकता घट रही है, जिससे गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। इन समस्याओं के बीच, अगर हमें भविष्य को सस्टेनेबल बनाना है, तो हमें सभी स्तरों पर समग्र और टोस कदम उठाने होंगे।

सस्टेनेबिलिटी की शुरुआत हमें अपनी रोजमर्रा की जीवनशैली से करनी होगी। इसमें सबसे पहले हमें अपनी उपभोग की आदतों पर ध्यान देना होगा। प्लास्टिक जैसी वस्तुएँ, जो पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँचाती हैं, उनका इस्तेमाल कम करना जरूरी है। इसके अलावा, 'मिनिमलिज्म' (कम से कम उपयोग करने की आदत) की ओर बढ़ना होगा, जिससे हम केवल वही खरीदें और उपयोग करें जो हमारे लिए वास्तव में आवश्यक हो। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का इस्तेमाल बढ़ाना भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जलविद्युत जैसे विकल्पों का इस्तेमाल न केवल जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करेगा, बल्कि यह

पर्यावरणीय प्रदूषण को भी कम करेगा। हमें अपने घरों में ऊर्जा-बचत उपकरणों का उपयोग करना चाहिए और ऊर्जा की खपत को कम करने के तरीकों को अपनाना चाहिए, जैसे दिन के उजाले में काम करने की आदत डालना।

जल, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, लेकिन हमारी लापरवाही के कारण यह तेजी से दुर्लभ होना जा रहा है। जलवायु परिवर्तन और मानवजनित गतिविधियों के चलते दुनिया के कई हिस्सों में जल संकट गहरा रहा है। ऐसे में जल की बचत और संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी है। हमें जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा और वर्षा जल संचयन जैसी तकनीकों को बढ़ावा देना होगा। इसके अलावा, जलस्रोतों की सफाई और पुनर्स्थापना भी जरूरी है ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल भंडार छोड़ सकें। कृषि में सस्टेनेबिलिटी लाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि परंपरागत कृषि प्रणाली ने हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर गहरा दबाव डाला है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है और जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है। जैविक खेती और परंपरागत कृषि प्रणालियों की ओर वापसी करके हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा, 'किसान-उपभोक्ता कड़ी' को भी सशक्त बनाना जरूरी है, ताकि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिले और उपभोक्ता को जैविक और ताजा उत्पाद प्राप्त हो सके। सस्टेनेबिलिटी का संदेश समाज के हर व्यक्ति तक पहुँचाना होगा। इसके लिए शिक्षा और जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण उपकरण हैं। हमें सस्टेनेबिलिटी से जुड़े मुद्दों पर स्कूलों, कॉलेजों और समाज में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने होंगे। बच्चों और युवाओं को पर्यावरणीय शिक्षा से जोड़ना होगा ताकि वे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सजग हो सकें। इसके साथ ही, हमें सस्टेनेबल तकनीकों और नवाचारों को भी बढ़ावा देना होगा, ताकि हम नई पीढ़ी को ऐसी तकनीकों से लैस कर सकें जो पर्यावरण के अनुकूल हों। सरकार की नीतियों का भी सस्टेनेबल विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे कानून और नीतियाँ बनाई जानी चाहिए जो प्राकृतिक संसाधनों के अनावश्यक दोहन को रोकें और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दें। सरकार को ऊर्जा की खपत, जल संरक्षण, और पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए कठोर मानदंड स्थापित करने चाहिए। साथ ही, उद्योगों को भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए,

ताकि वे अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं में सस्टेनेबल तरीकों का पालन करें।

सस्टेनेबल विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने में भी मदद करता है। आज भी दुनिया में करोड़ों लोग गरीबी, भूख, और असमानता से जूझ रहे हैं। ऐसे में सस्टेनेबिलिटी का लक्ष्य केवल पर्यावरण को बचाना नहीं है, बल्कि समाज के सभी वर्गों को विकास की धारा से जोड़ना है। हमें महिलाओं, हाशिए पर रहने वाले लोगों और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना होगा, ताकि वे अपनी जीवनशैली को सस्टेनेबल बना सकें और विकास की प्रक्रिया में बराबरी से भाग ले सकें।

सस्टेनेबिलिटी के मुद्दे केवल एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह एक वैश्विक चुनौती है। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का विनाश और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी समस्याएँ सभी देशों को प्रभावित करती हैं। ऐसे में हमें वैश्विक स्तर पर सहयोग और समझौते करने होंगे। पेरिस समझौते जैसी पहलें इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं, लेकिन यह जरूरी है कि सभी देश अपनी जिम्मेदारियों को समझें और मिलकर इन चुनौतियों का सामना करें। सस्टेनेबल भविष्य के लिए केवल सरकार और संगठनों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है। हम सभी को अपने स्तर पर छोटे-छोटे कदम उठाने होंगे, जैसे ऊर्जा की बचत करना, जल का संरक्षण करना, और सस्टेनेबल उत्पादों का उपयोग करना। इसके अलावा, हम अपने आसपास के लोगों को भी इस दिशा में प्रेरित कर सकते हैं, ताकि सामूहिक प्रयासों से हम एक सस्टेनेबल समाज का निर्माण कर सकें।

सस्टेनेबल भविष्य की दिशा में हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह जरूर है कि अगर हम अभी भी चेत गए और टोस कदम उठाए, तो हम एक सस्टेनेबल, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यह भविष्य न केवल हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए होगा, बल्कि हम सबके लिए एक बेहतर और स्वस्थ जीवन का आधार बनेगा। अब समय आ गया है कि हम सस्टेनेबिलिटी को अपनी जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा बनाएँ और इस ग्रह को एक बार फिर से संतुलित और समृद्ध बनाएँ।

(जगत फीचर्स)

पक्के आवास, किसानों को बोनस और महिलाओं को सौगात, देने के लिए प्रतिबद्ध हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

(पेज 1 का शेष)

सरकार को चरणबद्ध ढंग से महिलाओं, बच्चों, बेटीयों, युवाओं, बुजुर्गों और कामगारों के लिये लाभकारी योजनाओं का निर्माण कर उन्हें संबल देने का कार्य करने की आवश्यकता है। कानून व्यवस्था पर भी काफी ध्यान देना होगा। क्योंकि देखने में आ रहा है कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। जिसका लाभ विपक्ष लेना चाहता है। मुख्यमंत्री साय को इस विशेष विभाग पर भी खासी नजर रखनी होगी। कवर्धा की घटना ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को कठघरे में खड़ा किया है।

अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं, जो जमीनी स्तर पर लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं। ऐसी ही एक पहल है नियत नेलनार योजना, जो माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में आवास, अस्पताल, पानी, बिजली, पुल और स्कूल जैसे आवश्यक संसाधनों के विकास पर केंद्रित है। दूरदराज के आदिवासी इलाकों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास भी जारी हैं। भारत के सबसे कम साक्षर जिलों में से एक बीजापुर में माओवादियों द्वारा बंद किए गए 28 स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है। इसके अलावा, शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए स्थानीय बोलियों में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। 18 स्थानीय भाषाओं और बोलियों में पाठ्य पुस्तकों तैयार की जा रही हैं। पीएससी परीक्षा घाटाला को लेकर युवाओं के गुस्से और हताशा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की। शासकीय भूतों आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने से युवाओं के मन में खुशियां देखने को मिली हैं।

राज्यांश की व्यवस्था तुरंत की

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि "हमारी सरकार ने 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर को हमारे पहले कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। राज्यांश की व्यवस्था भी तुरंत की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि नए वित्तीय वर्ष के बजट में छत्तीसगढ़ को 8 लाख 46 हजार 931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति भारत सरकार से मिली है, जिसमें एसईसीटी 2011 के अंतर्गत 6 लाख 99 हजार 331 आवास और 1 लाख 47 हजार 600 आवास प्लस शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया। कहा कि "मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता और विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित होने वाले सभी लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।"

राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों को भी मिलेगा आवास

इसके साथ ही मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री जन्मन योजना का भी जिक्र किया करते हुए कहा कि विशेष पिछड़ी जनजाति जिन्हें राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी कहते हैं उनके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 हजार 64 आवास की स्वीकृति की गई है, जिनमें से कई पूर्ण हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि जनवरी से लेकर अब तक 1 लाख 99 हजार प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण किया जा चुका है और मोदी की गारंटी के अनुसार 18 लाख आवासों का निर्माण समयबद्ध रूप से पूरा किया जाएगा।

9520 आवासों का हुआ भूमिपूजन

खैरागढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत सिंधौरी में जिला स्तरीय आवास मेला एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम में शामिल हुए। देवांगन ने जिला में नवीन स्वीकृत 9520 आवासों का भूमिपूजन किया गया। सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को शुरूआत 1 अप्रैल 2016 से की गई थी। तब से लेकर आज पर्यंत तक लगातार गरीबों को पक्का आवास का लाभ मिल रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आवास के अलावा अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं पर सरकार काम कर रही है। गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मुफ्त चावल दिया जा रहा है। जो आगामी पांच साल तक लगातार दिया जाएगा। साथ ही घर-घर पेयजल पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश में साय सरकार महतारी वंदन

योजना के तहत महिलाओं के खातों में हर माह 1 हजार रुपये दे रही है।

महिला सशक्तिकरण

मुख्यमंत्री साय ने विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए अधिकांश वायदों को पूरा करने के लिए प्रारंभ कर दिया है। इसे कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। जब हम आधी आबादी की बात करते हैं तब उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलम्बन और सशक्तिकरण के लिए ठोस व दूरगामी रणनीति बनानी पड़ती है। प्रदेश के 70 लाख विवाहित महिलाओं के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण महतारी वंदन योजना से मिली है। प्रदेश के चारों तरफ विवाहित महिलाओं को हर माह एक हजार रूपए दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा विवाहित माताओं-बहनों के खातों में राशि देने के पीछे आर्थिक सशक्तिकरण करना, उनके आर्थिक हालात को बेहतर करना प्रमुख उद्देश्य है। यहां यह भी जरूरी है कि सिर्फ राशि देकर नारी शक्ति का उथान नहीं हो सकता है। महिलाओं को पुरा रोजगार जैसे कदम भी उठाना होंगे। जिससे वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके और स्वावलंबी बन सकें।

किसान कल्याण

हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है। और इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। प्रदेश की सरकार को चाहिए कि वह विशेष ध्यान के कल्याण के लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे वह आत्मनिर्भर हो सके। हालांकि साय सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों से 3100 रुपये प्रति किबंटल की दर से और 21 किबंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदने की गारंटी को पूरा करते हुए 32 हजार करोड़ रुपये के समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान किसानों के खातों में किया गया, वहीं 24 लाख 75 हजार किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत अंतर की राशि 13 हजार 320 करोड़ रूपए अन्तरित की गई। खरीफ सीजन में रिकॉर्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। इसके अलावा किसानों को दो साल के धान के बकाया बोनस राशि 03 हजार 716 करोड़ रूपए देने जैसे साहसिक निर्णय लिए हैं। सरकार बनते ही तैन्दूपता प्रति मानक बोरा 5 हजार 500 रूपए की गई, जिससे 12 लाख 50 हजार से अधिक तैन्दूपता संग्राहकों को लाभ मिल रहा है। सरकार की यह पहलें लाभादायक हो सकती हैं लेकिन इसके अलावा भी कई मामले हैं जिन पर काम करके किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है।

नक्सलवाद

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बहुत बड़ी समस्या है। प्रदेश के काफी जिले इस समस्या से जूझ रहे हैं। जिस बस्तर अंचल की पहचान सुंदर प्राकृतिक परिवेश और अकूत संसाधनों से है तथा यहां के भोलेभाले आदिवासियों की कला संस्कृति ने देश और दुनिया को अपनी ओर खींचा है। इस स्वर्ण को दूषित करने का काम कुछ नक्सलवादी कर रहे हैं। पिछली भूपेश सरकार ने इस समस्या पर कुछ काम नहीं किया। जिसके ही परिणाम रहे कि यह समस्या जस की तस रही। लेकिन प्रदेश में साय सरकार के अडिग निर्णय, बेहतर रणनीति का ही परिणाम है कि महज छह माह में 129 माओवादियों को सुरक्षा बलों के जवानों ने देर किया है, 488 गिरफ्तार हुए हैं 431 आत्म समर्पण किया और इस तरह बस्तर की उम्मीद की नई रौशनी देखने को मिलने लगी है। सुरक्षा और विकास के दोहरे मोर्चे पर काम करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इन्होंने प्रयासों का परिणाम है कि आज अनुपात के हिसाब से छत्तीसगढ़ का बस्तर देश में सबसे सैन्य संवेदनशील क्षेत्र बन चुका है, बस्तर डिजीवन में प्रत्येक 09 नागरिकों के पीछे एक पैरामिलिट्री का जवान है। जल्द ही इन क्षेत्रों में सुरक्षाबलों के 250 से ज्यादा कैम्प और नियत नेलनार से 58 नए कैम्प स्थापित होंगे ताकि सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं का दायरा बढ़ सके। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा बंद 28 स्कूल अब खुल गए हैं। इतना भर करते से नक्सलवाद की समस्या स्थायी रूप से हल नहीं होने वाली है। इसके लिए सरकार को कुछ ऐसे दूरगामी कदम उठाने होंगे जो जिससे जो लोग मुख्य धारा से भटक गये हैं वह वापिस मुख्य धारा में आ जायें।

जनजातीय वनवासियों के हितों के संरक्षण के लिए साय सरकार के प्रयास

(पेज 1 का शेष)

इस अभिनव पहल का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय युवाओं को विशेष प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करके उन्हें स्वावलंबी बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत युवाओं को पैराटेक्सोनीमी जैसे महत्वपूर्ण विषय में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो जैव विविधता संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है। ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पैराटेक्सोनीमी का एक ऐसा विधा है जिसमें जैविक अनुसंधान के लिए विभिन्न प्रजातियों की त्वरित पहचान और वर्गीकरण किया जाता है। छत्तीसगढ़ जैसे जैव विविधता से भरपूर क्षेत्रों में यह विधा विशेष रूप से उपयोगी है। इस प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षित युवा नेशनल पार्क गाइड, पर्यटक गाइड, नेचर कैंप मैनेजर, पारंपरिक चिकित्सक जैसे विभिन्न पेशों में काम कर सकते हैं एवं बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि हमारे राज्य में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जनजातियों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। जिसके उचित क्रियान्वयन से सभी लोगों को समय पर लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के वन बल प्रमुख वही, निवास राव ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के पीछे की अवधारणा को साझा करते हुए कहा कि यह पहल स्थानीय समुदायों को छत्तीसगढ़ की जैव विविधता संरक्षण में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रशिक्षण न केवल युवाओं के रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाता है, बल्कि स्थानीय वनस्पतियों और जीवों के बारे में पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने और इसे आगली पीढ़ी को सौंपने का भी अवसर प्रदान करता है।

पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी और संसाधन संरक्षण

छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष राकेश चतुर्वेदी ने इस पहल के व्यापक प्रभाव पर जोर देते हुए कहा कि यह कार्यक्रम सिर्फ एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नहीं है। यह छत्तीसगढ़ के जनजातीय युवाओं के लिए एक परिवर्तनकारी अवसर है। पैराटेक्सोनीमी में कोशल प्रदान करके हम एक ऐसी पीढ़ी को बढ़ावा दे रहे हैं जो न केवल अग्रसेन पर्यावरण के बारे में जानकार है, बल्कि उसे संरक्षित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव राजेश कुमार चंदेल, आईएफएस ने पर्यावरण संरक्षण में पैरा टेक्सोनीमी की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में कहा कि जैव संकेतक (बायो इंडिकेटर) पीछों की पहचान करके पैरा टेक्सोनीमी पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी और संसाधन संरक्षण में सहायता करती है।

विविन्न प्रजातियों की पहचान और दस्तावेजीकरण

इस प्रशिक्षण में भाग लेने वाले 53 प्रतिभागियों में से 40 जनजातीय युवा थे, जिनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि 10S2 से लेकर स्नातक तक थी और वे कांकेर, कोंडागांव, केसकात, भानुप्रतापपुर और नारायणपुर जैसे विभिन्न वन-मंडलों से आए थे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में 22 जुलाई से 18 अगस्त तक आयोजित किया गया था। 30 दिवसीय इस प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों ने कक्षा शिक्षण और फील्डवर्क दोनों में भाग लिया, जिसमें उन्होंने जंगल सफारी, मोहरगा, सिरपुर, अर्जुनी, बारनवापारा और उदती वन्यजीव अभयारण्य जैसे स्थलों पर जाकर विभिन्न प्रजातियों की पहचान और दस्तावेजीकरण किया। प्रशिक्षण के दौरान 93 प्रकार के मैक्रोफंगी, 153 प्रकार की वनस्पतियां, 47 औषधीय पौधे और 187 प्रकार के बीज का पहचान और दस्तावेजीकरण किया गया।

प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण

यह प्रशिक्षण प्रतिभागियों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. नीतू हर्मुख ने इस प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि सभी प्रतिभागी पैराटेक्सोनीमी में कोशल सीखने के लिए उत्सुक और तत्पर थे। कांकेर जिले के डुमरपानी गांव के 24 वर्षीय जनजातीय युवक त्रिभुवन कुमार करगा ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, "पैराटेक्सोनीमी" में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मेरा आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ा है। अब मेरे लिए आयु सृजन के नए रास्ते खुल गए हैं। इसी प्रकार ग्राम मुद्दोवा चारामा, कांकेर जिले के 39 वर्षीय जनजातीय समुदाय के प्रतिभागी राकेश नेताम ने कहा इस प्रशिक्षण ने हमारे जंगलों की जैव विविधता को समझने का ज्ञान दिया है। अब मुझे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति एक अहम जिम्मेदारी का एहसास होता है।

जनजातीय महिलाओं ने भी इस कार्यक्रम से काफी लाभ उठाया है। कोंडागांव जिले के बड़ेराजपुर विश्रामपुरी गांव की 22 वर्षीय महिला सु. दिव्या मरकाम ने कहा कि एक जनजातीय क्षेत्र की महिला के रूप में विशेष शिक्षा और रोजगार के अवसर सीमित रहे हैं। पैरा टेक्सोनीमी के इस प्रशिक्षण से मुझे एक नया अनुभव प्राप्त हुआ है, इससे हमें रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे एवं जनजातीय महिला सशक्तिकरण भी होगा। साथ ही साथ क्षेत्र की जैव विविधता को संरक्षित करने में भी मदद मिलेगी।

निरंतरता और स्थिरता भी सुनिश्चित

प्रशिक्षण की सफलता को देखते हुए छत्तीसगढ़ वन विभाग इस कार्यक्रम का विस्तार राज्य के अन्य हिस्सों जैसे जागदलपुर, सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग में भी करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा वन विभाग ने आगामी पैराटेक्सोनीमी प्रशिक्षण सत्रों के लिए पहले बैच के प्रतिभागियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में उपयोग करने की योजना बनाई है, जिससे न केवल पहले बैच के प्रतिभागियों को अनुभव और रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि कार्यक्रम की निरंतरता और स्थिरता भी सुनिश्चित होगी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम ने जैव विविधता संरक्षण में पहले ही महत्वपूर्ण परिणाम दिखाए हैं। प्रतिभागियों ने अपने स्थानीय क्षेत्रों में कई दुर्लभ वनस्पति और जीवों की प्रजातियों की पहचान और दस्तावेजीकरण किया है, जिसमें पूर्ण चमकदार खोल वाला एक अतृप्त कछुआ और दुर्लभ पौधे शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के जनजातीय युवाओं को सशक्त बनाने और राज्य की समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के इस प्रयास ने यह सुनिश्चित किया है कि हमारी प्राकृतिक धरोहरें और वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहेंगी।



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना

तकनीकी एवं अन्य व्यवसायिक शिक्षा में सहयोग

2 लाख रुपए वार्षिक आय से कम आय वाले परिवारों के छात्रों को 1% की ब्याज दर पर शिक्षा ऋण

माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण

छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए खुले अवसरों के द्वार

- नया रायपुर में आईटी हब
- पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया
- शासकीय भर्तियों में आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट

श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़



युवाओं की सरकार विष्णु देव सरकार



मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से
जुड़ने के लिए QR CODE स्कैन करें।

विष्णु के सुशासन से सँवर रहा छत्तीसगढ़

Visit us : [f ChhattisgarhCMO](#) [x ChhattisgarhCMO](#) [c ChhattisgarhCMO](#) [ChhattisgarhCMO](#) [f DPRChhattisgarh](#) [x DPRChhattisgarh](#) [www.dprcg.gov.in](#)

छत्तीसगढ़
समाचार